भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2143
11 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

बांधों एवं जलाशयों के ऊपरी (अपस्ट्रीम) क्षेत्रों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने की नीति

2143. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बांधों एवं जलाशयों के ऊपरी क्षेत्रों में मछली पालन की महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता के बारे में जानकारी है, जिससे आजीविका सृजन हो सकता है तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट नीति, दिशा-निर्देश अथवा योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संभावनाओं का उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों से परामर्श कर एक समर्पित नीति बनाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह

(क) से (ग) : मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत ऊपरी (अपस्ट्रीम) बाँधों और जलाशय क्षेत्रों में मात्स्यिकी और जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं क्योंकि यह देश में मत्स्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन करने के लिए, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और हितधारकों के परामर्श से मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने जलाशय मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए एक मॉडल दिशानिर्देश तैयार किया हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रसारित किया हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने जलाशय में मात्स्यिकी और जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की है, जैसे (i) 62,836 यूनिट केज और (ii) 545 हेक्टेयर पेन और (iii) 3.0 लाख हेक्टेयर से अधिक में फिंगरलिंग्स की स्टॉकिंग और (iv) 2,171.37 करोड़ रुपए की लागत से 23 जलाशयों का एकीकृत (इंटीग्रेटेड) विकास। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के समेकित विकास की घोषणा की गई है।

*****